नाम (Name): ..... टॉपिक नं॰ (Topic No.): 08

पंजीयन संख्या (Reg. No.) : ..... तारीख (Date) : .....

इस हाशिये में कुछ न लिखें Don't write anything in margin

इस हाशिये में कुछ न लिखें Don't write anything in margin

CASE STUDY-03

मान लीजिए कि आप ऐसी कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) हैं, जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। आपने विभाग को उपस्कर की पूर्ति के लिए अपनी बोली पेश कर दी है। आपके ऑफर की गुणता और लागत दोनों आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। इस पर भी सम्बन्धित अधिकारी टेंडर पास करने के लिए मोटी रिश्वत की मांग कर रहा है। ऑर्डर की प्राप्ति आपके और आपकी कम्पनी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्डर न मिलने का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बन्द कर देना। यह आपके स्वयं के कैरियर को भी प्रभावित कर सकता है। फिर भी, मूल्य-सचेत व्यक्ति के रूप में आप रिश्वत देना नहीं चाहते हैं।

रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने, तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने - दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। ये तर्क क्या हो सकते हैं? क्या इस धर्मसंकट से बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? यदि हाँ, तो इस तीसरे रास्ते की अच्छाइयों की ओर इंगित करते हुए उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, IAS-2014, 20 अंक)

Suppose you are the CEO of a company that manufactures specialized electronic equipment used by a government department. You have submitted your bid for the supply of this equipment to the department. Both the quality and cost of your offer are better than those of the competitors. Yet the concerned officer is demanding a hefty bribe for approving the tender. Getting the order is important both for you and your company. Not getting the order would mean closing a production line. It may also affect your own career. However, as a value-conscious person, You do not want to give bribe.

Valid arguments can be advanced both for giving the bribe and getting the order, and for refusing to pay the bribe and risking the loss of the order. What those arguments could be? Could there be any better way to get out of this dilemma? If so, outline the main elements of this third way, pointing out its merits.

(Answer in 250 words, IAS 2014, 20 Marks)

उत्तर :

उपरोक्त मामला एक नैतिक दुविधा को इंगित करता है, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित हैं-

1. व्यक्तिगत एवं सांगठनिक लाभ हेतु भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाए या फिर सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए उत्पन्न दुष्प्रभावों का सामना किया जाए।
2. अनैतिक साधनों का सहारा लेकर साध्य की सिद्धि या साधन की पवित्रता को बनाये रखना।

KGS : 704, Ground Floor, Main Road, Opposite Batra Cinema, Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph. No. : 9205777817

इस हाशिये में कुछ न लिखें Don't write anything in margin

इस हाशिये में कुछ न लिखें Don't write anything in margin

3. सरकारी ठेकों में पारदर्शिता का मुद्दा तथा निजी संस्थानों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का मुद्दा।
4. जवाबदेहिता बनाम विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता।

केस के समाधान का प्रथम रास्ता- रिश्वत देकर ऑर्डर प्राप्त कर लेना।

संबंधित तर्क -

i. इससे कम्पनी की उत्पादन प्रक्रिया, कर्मचारियों का हित और स्वयं का कैरियर भी सुरक्षित रहेगा।
ii. इससे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण उपकरण सरकारी विभाग को प्राप्त होगा। इससे सार्वजनिक हित पर भी प्रभाव पड़ेगा।

केस के समाधान का दूसरा रास्ता- रिश्वत नहीं देना और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने देना।

संबंधित तर्क -

i. रिश्वतखोरी की संस्कृति विकसित हो सकती है। इससे कम्पनी की छवि और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ii. मामला प्रकाश में आने पर कम्पनी ब्लैकलिस्ट हो सकती है, भारी जुर्माना लग सकता है। इससे कम्पनी के बंद होने का भी खतरा हो सकता है।
iii. घूस देने पर 'अंतरात्मा का संकट' पैदा होगा, इससे प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
iv. मोटी रिश्वत देने पर या तो उपकरण की लागत बढ़ेगी या उपकरण की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा।

केस के समाधान का तीसरा संभावित रास्ता -

i. कम्पनी के सीईओ होने के नाते मैं अपने उत्पाद की लागत के साथ-साथ गुणवत्ता और विशेषताओं को सार्वजनिक करूंगा ताकि अधिकारियों पर घटिया एवं महंगा उत्पाद न चुनने का दबाव हो।
ii. बोली लगाने (bid) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दबाव बनाना।
iii. व्हिसल ब्लोअर की मदद ताकि सरकारी विभाग में विद्यमान भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके।
iv. मोटी रिश्वत की मांग की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों से की जा सकती है ताकि भ्रष्ट आचरण में लिप्त अधिकारी को हतोत्साहित एवं दण्डित किया जा सके।
v. ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर RTI का सहारा लेना ताकि यह पता चल सके कि आखिर किन आधारों पर और कैसे दूसरी कम्पनी को ऑर्डर दिया गया?

इस प्रकार यह तीसरा विकल्प दुविधा से बाहर निकलने में अधिक मददगार है। दूसरा विकल्प भी अच्छा है परन्तु यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो वहाँ मौन होकर बैठना उचित नहीं है। तीसरा विकल्प वस्तुतः व्यक्तिगत हित, कम्पनी हित और सार्वजनिक हित तीनों में सामंजस्य स्थापित करता है।

■■■■

KGS : 704, Ground Floor, Main Road, Opposite Batra Cinema, Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph. No. : 9205777817